तैयारी | वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर कदम, दुग्ध क्षेत्र पांच प्रमुख सेक्टरों में शामिल

दुग्ध क्षेत्र के दम पर यूपी हासिल करेगा लक्ष्य

■ अजीत कुमार

लखनऊ। यूपी अपने दुग्ध क्षेत्र के बल पर वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा। इसके लिए सरकार ने दुग्ध क्षेत्र को शीर्ष पांच सेक्टर में शामिल किया है। इसके तहत प्रदेश में दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार से लेकर दूध की उत्पादकता बढ़ाने के कार्यों पर सरकार फोकस करेगी। इसकी शुरूआत उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद की ओर से कर दी गई है। परिषद ने प्रदेश के चार जिलों यथा, बुन्देलखण्ड में ललितपुर, मध्य यूपी में बाराबंकी, पूर्वांचल में वाराणसी तथा पश्चिमी यूपी में बरेली के चयनित ब्लॉकों में गर्भ परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

20 ब्लॉक में खोली जा रहीं गर्भ परीक्षण प्रयोगशालाएं

पशुधन विकास परिषद प्रदेश के चार जिलो के 20 ब्लॉकों में गर्भ परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर रहा है। इससे पशुपालकों को मात्र एक माह के भीतर पता चल जाएगा कि पशु गर्भ से है या नहीं। वर्तमान में पशु गर्भ से है इसका पता तीन माह बाद ही हो पाता है। इससे दो महीने का समय बचेगा। साथ ही दो ब्यांत के बीच के अंतर को 90 दिन का अन्तर कम किया जा सकेगा। वहीं प्रति ब्यांत कम से कम 250 लीटर दूध बढ़ेगा और पशुपालक को न्यूनतम 35000 रूपये की अतिरिक्त आय होगी।

दरअसल प्रदेश में दो लाख करोड़ का दुग्ध क्षेत्र का कारोबार है जिसमें अभी भी विस्तार की अपार सम्भावनाएं है। सरकार दूध की उत्पादकता को बढ़ाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करने जा रही हैं ताकि अगले तीन से चार वर्षों में दो लाख के कारोबार वाला यह क्षेत्र ढ़ाई से तीन लाख करोड़ तक पहुंच जाए। राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या दो करोड़ से अधिक है लिहाजा उत्पादकता में मामली वृद्धि से भी इस कारोबार में प्रति वर्ष 25 से 30 हजार करोड़ रूपये की वृद्धि हो सकती है। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद ने नस्ल सुधार के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। परिषद के 29 अक्तूबर को हुई निदेशक मण्डल की बैठक में इस दिशा में कई ठोस फैसले लिए गए।

नस्ल सुधार की दिशा में तेजी से बढ़ाए कदम: नस्ल सुधार की दिशा में पशुधन विकास परिषद टेस्ट ट्यूब एवं भ्रूण प्रत्यारोण तकनीक अपनाने पर जोर दे रहा है। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से केवल बछिया ही पैदा हो इसके लिए वर्गीकृत वीर्य (सेक्स सीमन) के डोज की व्यवस्था की जा रही है। परिषद सालाना एक करोड़ सेक्स सीमन डोज की व्यवस्था में जुट गया है।